

आवश्यक

संख्या: 05/2021/ 222 /12-2-2021-1/2019 टी0सी0-1

प्रेषक,

आलोक सिन्हा,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास विभाग, मत्स्य विभाग, समन्वय विभाग, पशुपालन विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, जल संसाधन एवं परती भूमि विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, लघु सिंचाई एवं भूजल विभाग, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, रेशम विभाग, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, कृषि विदेश एवं व्यापार विभाग, पंचायती राज विभाग, नमामि गंगे विभाग, सहकारिता विभाग, आद्योगिक विकास विभाग, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2 समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3 समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ:

दिनांक: 15 जनवरी, 2021

विषय: उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ0) नीति-2020 के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 35/2020/1899/12-2-2020-1/2019 टी0सी0 दिनांक 29 सितम्बर, 2020 के क्रम में उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादक संगठन नीति 2020 के क्रियान्वयन से संबंधित दिशा-निर्देश की प्रति संलग्नक सहित प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादक संगठन नीति 2020 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में तत्काल अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(आलोक सिन्हा)

कृषि उत्पादन आयुक्त।

संख्या: 05/2021/ (1)/12-2-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कुलपति, चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
2. कुलपति, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या।
3. कुलपति, वांटा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांटा।

4. कुलपति, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ।
5. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. सचिव (डी०ए०सी०डब्ल्यू), भारत सरकार।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. समन्वय राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. सचिव, जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. राज्य समन्वयक, यू०पी०डास्प द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. प्रबंध निदेशक, एस०एफ०ए०सी० द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. प्रबंध निदेशक, एन०सी०डी०एम० द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14. प्रबंध निदेशक, यू०पी० स्टेट एग्री इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
15. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, लखनऊ।
16. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, गोमती नगर, लखनऊ।
17. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू०पी० द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
18. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
19. समस्त प्रभारी, कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
20. प्रबंध निदेशक, इफ्को द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
21. प्रबंध निदेशक, कृभको द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आज्ञा से,
(अनिल दींगरा)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ0) नीति, 2020 के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश

प्रदेश के कृषक उत्पादन संगठन एवं व्यवसायिक गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु शासनादेश संख्या: 35/2020/1899/12-2-2020-1/2019/109 टी0सी0 दिनांक 29 सितम्बर, 2020 द्वारा उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादन संगठन नीति, 2020 निर्गत की गयी है।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। प्रदेश की दो तिहाई आबादी की आजीविका पूरी तरह से कृषि एवं सहाय्यित क्षेत्र पर निर्भर है। कृषि जोतों के आधार पर प्रदेश में 2.38 करोड़ कृषक परिवार हैं। इनमें से लगभग 79 प्रतिशत सीमान्त किसान परिवार तथा 13 प्रतिशत लघु सीमान्त कृषक परिवार सम्मिलित हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को “एक ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था” के रूप में स्थापित करने में “उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादक संगठन नीति-2020” एक सशक्त साधन के रूप में स्थापित की गयी है। इस नीति की मूल आवधारणा प्रदेश के किसान को कृषक उद्यमी के रूप में संगठित कर “खेती-बाड़ी” की सनातन भारतीय परम्पराओं को पुनः स्थापित करते हुये प्रदेश के प्रत्येक कृषक परिवार को पूर्ण आत्मनिर्भर बनाना है।

1.1 परिभाषाएँ/संक्षेपाक्षरों का विवरण :

एफ0पी0ओ0	: फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन
एफ0पी0सी0	: फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी
पैन कार्ड	: परमानेन्ट एकाउण्ट नम्बर
आर0ओ0सी0	: रजिस्टार आफ कम्पनीज
टी0ए0एन0	: टैक्स डिडक्शन एण्ड कलेक्शन एकाउण्ट नम्बर
ई0पी0एफ0	: इम्पलाइज प्राविडेन्ट फण्ड
ई0एस0आइ0सी0	: इम्पलाइज स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेट एसोशियेशन
ए0टी0एम0	: सहायक तकनीकी प्रबन्धक
बी0टी0एम0	: ब्लाक तकनीकी प्रबन्धक

2.0 कृषक उत्पादक संगठन पंजीयन अधिनियम, पंजीयन की प्रक्रिया :

कृषक उत्पादक संगठन, कम्पनी अधिनियम 1956 (यथा संशोधित 2013) की धारा 465 (1) के भाग 581 अथवा उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति पंजीयन अधिनियम 1965 (यथा संशोधित) के अधीन पंजीकृत व्यावसायिक निकाय है। इसमें कृषक/प्राथमिक उत्पादक अथवा उनके समूह संगठित होकर कृषि एवं कृषि सहाय्यित (Agriculture & Agriculture allied) क्षेत्रों में वित्तीय निवेश तथा अद्यतन तकनीकी का प्रयोग कर सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला (Value Chain) की स्थापना का मार्ग सुगम तरीके से स्थापित कर स्थायी आर्थिक समृद्धि तथा सतत विकास की परिकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने हेतु प्रयास करते हैं।

2.1 एफ0पी0ओ0 के पंजीयन की प्रक्रिया :

जैसा कि ऊपर वर्णित है, एफ0पी0ओ0 का पंजीयन कम्पनी अधिनियम 1956 (यथा संशोधित 2001) अथवा उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति पंजीयन अधिनियम 1965 (यथा संशोधित) में किये जाने की व्यवस्था प्रचलित है। "VOCAL FOR LOCAL" एवं "LOCAL TO GLOBAL" परिकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने हेतु कम्पनी अधिनियम 1956 (यथा संशोधित 2013) को प्राथमिकता के साथ लागू करने की आवश्यकता है क्योंकि इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियों की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक मान्यता है। साथ ही कृषि तथा कृषि सहाय्यित क्षेत्र के समस्त उत्पादों की सकल मूल्य श्रृंखला स्थापना करने की पूरी स्वतंत्रता है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश राज्य सहकारिता पंजीयन अधिनियम 1965 (यथा संशोधित) में एफ0पी0ओ0 के पंजीयन का प्रश्न है इसमें कार्य विशेष के लिये ही पंजीयन की व्यवस्था है जैसे— मत्स्य पालन सहकारी समिति, कुक्कुट पालन सहकारी समिति, औद्योगिक सहकारी समिति इत्यादि। साथ ही इस प्रकार की समितियों के पंजीयन का प्रमाण—पत्र निर्गत करने का अधिकार सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष को प्रदत्त है।

उक्त के आलोक में कम्पनी अधिनियम 1956 (यथा संशोधित 2013) के अन्तर्गत ही पंजीयन की प्रक्रिया तथा उसमें होने वाले व्यय का विवरण प्रस्तुत है।

2.2 पंजीयन की प्रक्रिया:

कृषक उत्पादक संगठन का पंजीयन, कम्पनी अधिनियम 1956 (यथा संशोधित 2013) में करने हेतु न्यूनतम 10 किसानों द्वारा एफ0पी0ओ0 के गठन की कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रपत्र आवश्यक होते हैं:—

- (i) समस्त 10 किसानों के पैन कार्ड।
- (ii) समस्त 10 किसानों के आधार कार्ड।
- (iii) समस्त 10 किसानों के बैंक पासबुक की अद्यतन इन्ट्री सहित पासबुक।
- (iv) समस्त 10 किसानों की दो-दो फोटो।
- (v) समस्त 10 किसानों के खेत की खतौनी तथा कृषि विभाग द्वारा प्रदत्त कृषक प्रमाण—पत्र (उचित प्रारूप में कृषि विभाग से)
- (vi) समस्त 10 किसानों का मोबाइल फोन नम्बर तथा ई—मेल।

उक्त समस्त विवरण के अलावा निम्नलिखित अन्य सूचनायें भी अति आवश्यक हैं:—

- (i) फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के दो प्रस्तावित नाम।
- (ii) कुछ अतिरिक्त उद्देश्य (यदि आवश्यक हो)।
- (iii) प्रस्तावित पंजीकृत कार्यालय का अद्यतन जमा विद्युत बिल की प्रति।

(iv) निदेशक तथा अंश धारकों की संख्या

कम्पनी अधिनियम 1956 (यथा संशोधित 2013) में फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी (FPC) के पंजीयन के समय न्यूनतम 05 निदेशक तथा 05 शेयर होल्डर सदस्य होते हैं। भविष्य में यथा आवश्यकता अधिकतम 15 निदेशक हो सकते हैं किन्तु शेयर होल्डर की संख्या की अधिकतम सीमा के बारे में अधिनियम में कोई स्पष्ट विवरण नहीं है। फिर भी कृषक उत्पादक संगठन में सुचारु व्यावसायिक प्रबन्धन हेतु अधिकतम 1000 शेयर होल्डर की सीमा निर्धारित किया जाना उचित होगा।

कम्पनी अधिनियम 1956 (यथा संशोधित 2013) में पंजीयन की समस्त कार्यवाही प्रशिक्षित चार्टर्ड एकाउण्टेंट अथवा कम्पनी सेक्रेटरी द्वारा पूर्ण की जाती है। इस हेतु समस्त 05 निदेशकों तथा 05 शेयर होल्डर सदस्यों के डिजीटल हस्ताक्षर भी बनवाना पड़ता है। पंजीयन की समस्त कार्यवाही ऑन-लाइन पूर्ण की जाती है।

2.2.1. कृषक उत्पादक कम्पनी के लक्ष्य/उद्देश्य का निर्धारण :

किसी भी कृषक उत्पादक कम्पनी के उद्देश्यों का निर्धारण कृषि एवं कृषि सहाय्यित क्षेत्र के समस्त क्रियाकलापों को लक्ष्य करते हुये निर्धारित किया जायेगा तथा इसका एक मॉडल स्मृति पत्र (Memorandum of Association) तथा नियमावली (Article of Association) संलग्नक-01 पर प्रस्तुत है।

2.3 पंजीयन शुल्क तथा उसके भुगतान की प्रक्रिया :

कम्पनी अधिनियम 1956 (यथा संशोधित 2013) में एफ0पी0ओ0 के पंजीयन तथा उसे पूर्ण क्रियाशील बनाये रखने हेतु कुल न्यूनतम व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

2.3.1 एफ0पी0ओ0 को कम्पनी के रूप में पंजीयन तथा उसकी निरन्तरता बनाये रखने हेतु प्रथम वर्ष में जमा किये जाने वाले फार्म :

एफ0पी0ओ0 के पंजीयन हेतु कम्पनी की अधिकृत पूंजी की घोषणा के पंजीयन के समय निदेशक को करनी पड़ती है। रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज भारत सरकार द्वारा रू0 1.0 लाख से रू0 10.00 लाख तक अधिकतम अधिकृत पूंजी के सापेक्ष एक समान पंजीयन शुल्क आन लाइन जमा किया जाता है। पंजीयन हेतु निम्नलिखित मदों में व्यय प्रस्तावित है:-

2.3.1.1 समस्त 05 निदेशकों तथा 05 शेयर होल्डर के डिजीटल हस्ताक्षर पर व्यय।

2.3.1.2 कम्पनी के नाम की स्वीकृति हेतु व्यय।

2.3.1.3 कम्पनी का पंजीयन शुल्क के सापेक्ष व्यय तथा चार्टर्ड एकाउण्टेंट/कम्पनी सेक्रेटरी की प्रोफेशनल फीस जिसमें (कम्पनी का संविधान तैयार करना, पंजीयन के उपरांत उसकी 10 प्रतियां छपवाकर कम्पनी के निदेशक को उपलब्ध कराना सम्मिलित है।

2.3.2 फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के पंजीयन के उपरांत उसकी विधिक निरन्तरता बनाये रखने हेतु अलग-अलग फार्म जमा करने होते हैं जिसके साथ आवश्यक शुल्क भी जमा करना होता है। इसमें निम्नलिखित फार्म सम्मिलित हैं:-

2.3.2.1 प्रथम 30 दिन के अन्दर आडिटर नियुक्ति हेतु फार्म ADT-01 रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज भारत सरकार को ऑन-लाइन जमा करने पर व्यय।

2.3.2.2 फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के पंजीयन के 180 दिन के अन्दर व्यवसाय प्रारम्भ करने की सूचना रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज के कार्यालय में फार्म नं0 INC-20A जमा करने पर व्यय।

2.3.2.3 फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के पंजीयन के 180 दिन के अन्दर सी0इ0ओ0 की तैनाती की सूचना रजिस्ट्रार आफ कम्पनी के कार्यालय में फार्म नं0 QIR-12 जमा करने पर व्यय।

2.3.2.4 प्रथम वर्ष की वार्षिक Compliance तथा आयकर विवरणिका क्रमशः फार्म AOC-4 फार्म MGT-7, फार्म PAS-3, फार्म निदेशकों की KYC जमा करने पर सम्मिलित है।

2.3.3 एफ0पी0ओ0 के पंजीयन तथा उससे सम्बन्धित प्रथम वर्ष की विधिक कार्यवाही पूर्ण करने हेतु लगभग रू0 36,500/- का न्यूनतम व्यय निहित है।

2.4 द्वितीय वर्ष तथा आगे के वर्षों में रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज के नियमों का अनुपालन (कम्प्लायन्सेज), आयकर विवरणिका जमा तथा वार्षिक बैलेन्स शीट आडिट की व्यवस्था करना :

फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के गठन के पश्चात द्वितीय वर्ष तथा आगे के वर्षों में क्रमशः फार्म AOC-4, फार्म MGT-7, फार्म PAS-3 रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज की वेबसाइट पर ऑन-लाइन जमा करने के साथ-साथ समस्त निदेशकों की KYC, तथा बैलेन्स शीट आडिट कराना अति आवश्यक होगा। यह कार्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट/कम्पनी सेक्रेटरी के द्वारा पूर्ण किया जाता है। द्वितीय वर्ष तथा आगे के वर्षों में अनुमानतः लगभग रू0 11,500/- का न्यूनतम व्यय निहित है।

नोट:

1. डिजिटल सिग्नेचर की वैधता दो वर्ष की है। भविष्य में सिर्फ एक निदेशक के डिजिटल सिग्नेचर का नवीनीकरण कराना होगा। एक डिजिटल सिग्नेचर पर कुल रू0 1000/- का व्यय आता है।

2. फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के निदेशकों को यह परामर्श दिया जाना चाहिये कि वे अपना मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल न बदलें। अन्यथा के0वाई0सी0 कराने पर व्यय अतिरिक्त अधिभार होगा।

3.0 कृषक उत्पादक संगठनों की स्थापना एवं उन्हें सत्त रूप से क्रियाशील बनाये जाने हेतु शासकीय व्यवस्था का स्वरूप एवं सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं की भूमिका :

प्रदेश में कृषक उत्पादक संगठनों की स्थापना तथा उन्हें सत्त रूप से क्रियाशील बनाये जाने हेतु शासनादेश सं0-35/2020/1899/12-2-2020-1/2019 टी0सी0 दिनांक 29 सितम्बर, 2020 "उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादक संगठन नीति-2020" तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न स्तरीय समितियों का गठन शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-58/2020/ 2021/12-2-2020-1/2019 दिनांक 04 नवम्बर, 2020 (सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2020/2133/12-2-2020-1/2019 दिनांक 27 नवम्बर, 2020) द्वारा किया जा चुका है। विभिन्न स्तरीय समितियों द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम को मिशन मोड में समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित किये जाने हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की जा रही है:-

3.1 राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई :

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या -58/2020/2021/12-2-2020-1/2019 दिनांक 4 नवम्बर, 2020 (सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2020/2133/12-2-2020-1/2019 दिनांक 27 नवम्बर, 2020) द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई का निम्नानुसार गठन किया जा चुका है :-

क्र0सं0	नाम	पद
1.	कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधानविभाग/उद्यान/पशुपालन/	सदस्य

	मत्स्य/सहकारिता/कृषिविपणन/ग्राम्य विकास/पंचायती राज	
3.	प्रमुख सचिव न्याय विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
4.	प्रतिनिधि नाबार्ड	सदस्य
5.	संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	सदस्य
6.	दो विशेषज्ञ, कृषि विश्वविद्यालय/संस्थान	सदस्य
7.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य सचिव
8.	वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ	सदस्य
9.	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट, उत्तर प्रदेश	सदस्य

राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धक इकाई द्वारा फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के गठन तथा उसे सतत रूप से क्रियाशील बनाये जाने हेतु लिये गये नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा गठित फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के क्रियाकलापों की समीक्षा, उनके समक्ष आने वाले कठिनाइयों के निस्तारण तथा शासन द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं/परियोजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ पहुँचाने हेतु राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई के प्रत्यक्ष संरक्षण तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में एक क्रियान्वयन सेल कृषि विभाग मुख्यालय पर गठित किया जायेगा। इसका संगठनात्मक ढाँचा उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 29 सितम्बर, 2020 के अनुसार होगा।

राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई कम्पनी सेक्रेटरी की सेवाओं हेतु कम्पनी सेक्रेटरी का पैनल गठित करके उपलब्ध करायेगी और दरें भी औचित्यपूर्ण तरीके से निर्धारित करेगी जिनकी सेवायें कृषि उत्पादन संगठनों द्वारा लिया जा सकेगा। राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई कृषि उत्पादन संगठनों को पंजीकरण करने में हैण्ड-होल्डिंग/यथोचित सहायता उपलब्ध करायेगी।

3.2 राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा क्रियान्वित किये जाने वाले महत्वपूर्ण क्रियाकलाप :

कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक नियंत्रण में मुख्यालय स्तर पर नीतिगत समन्वय हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई की स्थापना कार्यालय ज्ञाप संख्या -58/2020/2021/12-2-2020-1/2019 दिनांक 4 नवम्बर, 2020 (सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2020/2133/12-2-2020-1/2019 दिनांक 27 नवम्बर, 2020) द्वारा की गयी है। एफ०पी०ओ० कार्यक्रम के सफल, समयबद्ध तथा निरन्तर संचालन में इस इकाई की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा क्रियान्वित किये जाने वाले महत्वपूर्ण क्रियाकलाप निम्नवत् हैं:-

3.2.1 फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के पंजीयन हेतु कार्यवाही करना :

जनपद स्तरीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट से प्राप्त ऑन-लाइन सूचना के आधार पर प्राथमिक प्रोसेसिंग कर रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज के वेबसाइट पर फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के पंजीयन हेतु ऑन-लाइन आवेदन प्रस्तुत करना, पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण होने पर उसकी सूचना सम्बन्धित फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के प्रथम निदेशक को ई-मेल तथा मोबाइल संचार के माध्यम से प्रेषित करने का दायित्व राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा वहन किया जायेगा।

3.2.2 रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज से जुड़ी प्रथम वर्ष की समस्त विधिक कार्यवाही को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करना :

राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई में कार्यरत/सम्बद्ध चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा सम्बन्धित कम्पनी के पंजीयन के पश्चात उसमें आडिटर नियुक्ति हेतु फार्म ADT-01, व्यवसाय प्रारम्भ करने की सूचना हेतु फार्म नं० INC-20A, सी०ई०ओ० की तैनाती हेतु फार्म नं० QIR-

12, प्रथम वर्ष की वार्षिक Compliance तथा आयकर विवरणिका क्रमशः फार्म AOC-4 फार्म MGT-7, फार्म PAS-3, तथा निदेशकों की KYC प्रपत्र तैयार कर आन-लाइन रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज की वेबसाइट पर जमा कर उसकी पावती सुनिश्चित करते हुये उसकी प्रति सम्बन्धित फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी को भी उपलब्ध करायेंगे। प्रथम वर्ष की विधिक कार्यवाही पूर्ण करने में ₹0 11500/- का व्यय निहित है।

3.2.3 फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी को क्रियाशील बनाने (Hand Holding) तथा शेयर होल्डर्स की संख्या बढ़ाने में सहयोग प्रदान करना :

वर्तमान परिवेश में किसान विभिन्न सामाजिक पर्यावरणीय एवं तकनीकी कारणों से आर्थिक विपन्नता के दौर से गुजर रहा है। इन परिस्थितियों में फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के गठन के तत्काल पश्चात प्रदेश में सफलतापूर्वक संचालित पर्यावरण अनुकूल कृषि एवं औद्योगिकी क्रियाकलापों से उसे जोड़ दिया जायेगा।

उदाहरणार्थ— संगंध कृषि कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्बन्धित फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के संस्थापक 10 किसानों को उनके 10 एकड़ रकबे पर लेमनग्रास की कृषि हेतु आवश्यक इनपुट एवं एक आसवन संयंत्र (01 टन क्षमता) की स्थापना से फसल लगाने के प्रथम 120 दिन पश्चात वर्तमान दर पर सम्बन्धित किसान को प्रथम तिमाही में औसतन लगभग ₹0 30000/- की प्राप्ति होगी। साथ ही यह फसल प्रत्येक तिमाही अन्तराल पर आगामी पाँच वर्षों तक सम्बन्धित किसान को लाभ पहुंचाती रहेंगी। इसी प्रकार की अन्य संगंध एवं औषधीय फसलें भी हैं जिन्हें मार्जिनल भूमि पर भी पर्यावरण की विषम परिस्थितियों में आसानी से पैदा किया जा सकता है।

सम्बन्धित ए0टी0एम0/बी0टी0एम0 के समन्वय/सहयोग से उक्त उपलब्धि को क्षेत्रीय किसानों में व्यापक रूप से प्रचारित/प्रसारित किया जायेगा। तदोपरान्त प्रथम छमाही के अन्त तक प्रत्येक फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी में कम से कम 500 शेयर होल्डर किसान सम्मिलित किये जायेंगे। एक प्राथमिक शेयर होल्डर को न्यूनतम 10 शेयर तथा अधिकतम 20 शेयर प्रदान किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार गठित फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी को पूर्ण क्रियाशील बनाये जाने हेतु राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई में सम्बद्ध विषयवस्तु विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न शासकीय विभागों से समन्वय कर उनके द्वारा संचालित विकास योजनाओं/परियोजनाओं से कन्वर्जेन्स सपोर्ट प्राप्त किया जायेगा। इस प्रयास से गठित फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के व्यवसायिक क्रियाकलाप तत्काल प्रारम्भ हो जायेंगे। इससे फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के गठन संबंधी भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइड-लाइन्स में वर्णित वित्तीय व्यय की तुलना में अल्प व्यय में ही फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के गठन से लेकर उसे क्रियाशील बनाये जाने का कार्य पूर्ण हो जायेगा।

3.2.4 विभागीय योजनाओं से कन्वर्जेन्स सहायता तथा सम्बन्धित विभागों का दायित्व :

प्रदेश में एफ0पी0ओ0 कार्यक्रम को पूर्ण सफल बनाने हेतु राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई के समन्वय से उ0प्र0 शासन के विभिन्न विभाग अपनी विभागीय योजनाओं /परियोजनाओं में यथा आवश्यकता कन्वर्जेन्स सहायता प्रदान करने हेतु शासनादेश/क्रियान्वयन दिशा निर्देश निर्गत करेंगे।

वर्तमान में कृषि, उद्यान, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन इत्यादि से जुड़ी परियोजनाओं का कन्वर्जेन्स/लाभ प्राप्त करने हेतु व्यक्तिगत लाभार्थीपरक, किसान परक प्रस्ताव आन-लाइन जमा करना पड़ता है। इस कारण से फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के निदेशकों को अनेक प्रशासनिक एवं वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान हेतु विभिन्न विभागों द्वारा संचालित डी0बी0टी0 योजना के पोर्टल पर फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी, को भी लाभार्थी के रूप में दर्ज करते हुये उत्तर प्रदेश शासन के कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के विभागों के क्रमशः ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, राज्य औषधि पादप बोर्ड, उ0प्र0, मत्स्य पालन विभाग, उ0प्र0 शासन, उद्यान

एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ०प्र० शासन, कृषि विभाग, कृषि शिक्षा एवं कृषि शोध, उ०प्र० शासन, पशुधन विभाग, उ०प्र० शासन, दुग्ध विकास विभाग, उ०प्र० शासन, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, जल संसाधन विभाग, उ०प्र० शासन, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन, पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० शासन, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ०प्र० शासन, रेशम विभाग, उ०प्र० शासन, लघु सिंचाई एवं भूजल विभाग, उ०प्र० शासन, परती भूमि विकास, उ०प्र० शासन के अतिरिक्त शासन के साथ-साथ अन्य विभागों द्वारा भी अपनी विकास योजनाओं/परियोजनाओं में फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के सत्त विकास के लिए कन्वर्जेन्स सुविधा प्रदान करने हेतु आदेश/शासनादेश निर्गत करेंगे। सम्बन्धित विभागों एवं उनके द्वारा संचालित योजनाओं/परियोजना का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों को कन्वर्जेन्स सहायता प्रदान करने वाले विभाग	वर्तमान में संचालित योजना/परियोजना का नाम
1.	ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र०	<ul style="list-style-type: none"> • कृषक सशक्तिकरण परियोजना • आजीविका मिशन • किसानोंपयोगी अन्य विभागीय योजनाएँ।
2.	राज्य औषधि पादप बोर्ड, उ०प्र०	<ul style="list-style-type: none"> • औषधीय कृषि योजना • औषधीय नर्सरी योजना • औषधीय बाजार की स्थापना • औषधीय कृषि प्रशिक्षण योजना • औषधीय उत्पाद क्रेता/विक्रेता सम्मेलन • किसानोंपयोगी अन्य विभागीय योजनाएँ।
3.	मत्स्य पालन विभाग, उ०प्र०	<ul style="list-style-type: none"> • प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना • किसानोंपयोगी अन्य विभागीय योजनाएँ।
4.	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ०प्र०	<ul style="list-style-type: none"> • औद्योगिक मिशन कार्यक्रम • खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रम • फूड-पार्क योजना • मिशन फॉर इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट फार हार्टीकल्चर • पान विकास कार्यक्रम • किसानोंपयोगी अन्य विभागीय योजनाएँ।
5.	कृषि विभाग, उ०प्र०	<ul style="list-style-type: none"> • एन०एफ०एस०एम०, • मिनी मिशन ऑन ऑयल सीड्स, • दृष्टि योजना, • आर०के०वी०वाई०, • पी०के०वी०वाई०,

		<ul style="list-style-type: none"> • पी0एम0 कुसुम योजना, • नमामि गंगे योजना, • प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फार इन-सी-टू मैनेजमेंट ऑफ क्राप रेजड्यू, • एस0एम0ए0एम0, • बी0जी0आर0ई0आई0, • प्रमाणित बीज तथा खाद एवं कीट नाशक फुटकर बिक्री केन्द्र की स्थापना हेतु लाइसेंस निर्गत करना। • किसानोंपयोगी अन्य विभागीय योजनाएँ।
6.	पशुधन विभाग, उ0प्र0	<ul style="list-style-type: none"> • पशुधन विकास कार्यक्रम • कुक्कुट पालन योजना • दुग्ध विकास योजना • बैक यार्ड कुक्कुट पालन योजना • जेनेटिक इम्प्रूवमेंट आफ सीप एण्ड गोट • नेशनल लाइव स्टाक मिशन के अन्तर्गत इन्वोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी लो इनपुट टेक्नालाजी बर्ड योजना, • नेशनल लाइव स्टाक मिशन के अन्तर्गत इन्वोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी ब्रयालर बर्ड योजना, • किसानोंपयोगी अन्य विभागीय योजनाएँ।
7.	दुग्ध विकास विभाग, उ0प्र0	<ul style="list-style-type: none"> • दुग्ध विकास योजना • किसानोंपयोगी अन्य विभागीय योजनाएँ।
8.	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0	<ul style="list-style-type: none"> • माइनर फारेस्ट प्रोड्यूस संग्रहण एवं बिक्री योजना • नर्सरी स्थापना कार्यक्रम • नेशनल एडाप्टेशन फण्ड ऑन क्लाइमेट चेंज • नेशनल बम्बू मिशन कार्यक्रम • किसानोंपयोगी अन्य विभागीय योजनाएँ।
9.	जल संसाधन विभाग, उ0प्र0	<ul style="list-style-type: none"> • वर्षा जल संचयन योजना • नदी/वाटर बाडी पुनर्रोधार योजना • नमामि गंगे योजना • किसानोंपयोगी अन्य विभागीय योजनाएँ।
10.	समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0	<ul style="list-style-type: none"> • जन जातीय विकास कार्यक्रम • वन-धन योजना

		<ul style="list-style-type: none"> ● किसानोंपयोगी अन्य विभागीय योजनाएँ।
11.	पंचायतीराज विभाग, उ०प्र०	<ul style="list-style-type: none"> ● गोवर्धन योजना ● किसानोंपयोगी अन्य विभागीय योजनाएँ।
12.	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ०प्र०	<ul style="list-style-type: none"> ● स्फूर्ति योजना ● क्लस्टर विकास योजना ● प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना ● मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना ● किसानोंपयोगी अन्य विभागीय योजनाएँ।
13.	रेशम विभाग, उ०प्र०	<ul style="list-style-type: none"> ● शिल्क उत्पादन कार्यक्रम ● किसानोंपयोगी अन्य विभागीय योजनाएँ।
14.	लघु सिंचाई एवं भूजल विभाग, उ०प्र०	<ul style="list-style-type: none"> ● मध्यम गहरे नलकूप योजना ● गहरे नलकूप योजना ● इन-वेल-रिंग बोरिंग योजना ● सरफेस पम्पसेट योजना ● चेक डैम एवं ग्राऊंड वाटर रिचार्जिंग योजना ● ब्लास्ट वेल योजना ● प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
15.	परती भूमि विकास, उ०प्र०	<ul style="list-style-type: none"> ● प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरसेड डेवलपमेन्ट कम्पोनेन्ट) ● किसानोंपयोगी अन्य योजनाएँ।
16.	कृषि शिक्षा एवं कृषि शोध, उ०प्र०	<ul style="list-style-type: none"> ● कृषि विश्वविद्यालयों के इक्सटेंशन डिपार्टमेंट द्वारा संचालित योजना। ● कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा संचालित योजनाएँ। ● यू०पी०सी०ए०आर० (यू०पी० काउंसिल फार एग्रीकल्चर रिसर्च) द्वारा संचालित विभिन्न कृषि शोध एवं विकास योजनाएँ।
17.	उ०प्र० कृषि विवधीकरण परियोजना	<ul style="list-style-type: none"> ● पी०के०वी०वाई० के अन्तर्गत गठित कृषक समूहों को एफ०पी०ओ० के रूप में पंजीकृत कराना। ● नमामि गंगे परियोजना के अन्तर्गत गठित कृषक समूहों को एफ०पी०ओ० के रूप में पंजीकृत कराना। ● किसानोंपयोगी अन्य विभागीय योजनाएँ।

उपरोक्त के अलावा अन्य विकास विभागों द्वारा समय-समय पर ग्रामीणों एवं किसानों के सत्त विकास हेतु जारी होने वाली योजनाओं/परियोजनाओं के लाभार्थी समूह में फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों को भी अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जायेगा।

3.2.5 फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों को संचालन हेतु बैंक ऋण उपलब्ध कराने में सहयोग करना :

उ०प्र० कृषक उत्पादक संगठन नीति-2020 के क्रम में पूर्व से कार्यरत कृषि उत्पादक संगठनों को नीति के लागू होने की तिथि से तथा नये कृषि उत्पादक संगठनों के कम्पनी एक्ट अथवा सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होने के पश्चात आगामी 03 वर्षों में व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु अधिकतम रुपये 5.00 लाख तक के बैंक ऋण पर प्रभावी ब्याज दर पर 04 प्रतिशत का अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए कृषक उत्पादक संगठन में न्यूनतम 150 अंशधारक कृषक होना आवश्यक होगा।

3.2.6 रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज तथा आयकर विभाग एवं अन्य विभागों की विधिक विवरणी ससमय तैयार कर आन लाइन जमा करना:

राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई से सम्बद्ध चार्टर्ड एकाउण्टेंट सम्बन्धित फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के बैंक खाते तथा अन्य प्राप्तियों/खर्चों के विवरण की साफ्ट कापी सम्बन्धित फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी से आन लाइन प्राप्त करेंगे। यथा आवश्यकता जनपद स्तरीय परियोजना प्रबन्ध इकाई की भी सहायता प्राप्त करेंगे, जिससे निर्धारित समय सीमा में समस्त आवश्यक विधिक/वित्तीय प्रपत्र/फार्म तैयार कर सम्बन्धित विभागों को आन-लाइन जमा कर दिया जाये। पावती रसीद का रिकार्ड सम्बन्धित एफ०पी०ओ० के साथ-साथ राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई में भी सुरक्षित रखा जायेगा।

कम्पनी के गठन के पश्चात प्रारम्भ के तीन वर्षों में यह कार्य राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धक इकाई स्तर से ही पूर्ण किया जायेगा। कालान्तर में इस कार्य हेतु फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को प्रशिक्षित कर विकेन्द्रीकृत रूप से प्रत्येक फार्मर प्रोड्यूसर को ही अपने स्तर पर रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज एवं आयकर विभाग की समस्त विधिक/वित्तीय प्रपत्र/फार्म विवरण इत्यादि ससमय तैयार कर ऑन लाइन जमा करने हेतु प्रेरित होंगे/किया जायेगा।

3.2.7 पूर्ण रूप से क्रियाशील एवं सफल फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों का भ्रमण :

राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण रूप से क्रियाशील एवं सफल फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के भ्रमण कार्यक्रम का समन्वय भी राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई स्तर पर किया जायेगा। इस प्रयास से कम्पनी के निदेशक किसानों एवं कम्पनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों का उत्साहवर्धन होगा। उन्हें अपने परम्परागत कृषि एवं औद्यानिकी क्रियाकलापों से हटकर कुछ अतिरिक्त करने तथा सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला की स्थापना करने का सुअवसर प्राप्त होगा। अन्तर्जनपदीय भ्रमण कार्यक्रम वर्ष में दो बार अन्तर्राज्यीय भ्रमण कार्यक्रम वर्ष में एक बार आयोजित किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में सहभागिता आधार पर भ्रमण कार्यक्रमों की संख्या बढ़ायी जा सकती है। भ्रमण कार्यक्रमों का कैलेंडर प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में ही राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा जारी कर दिया जायेगा। वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक जनपद से पूर्ण क्रियाशील फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों की सूची राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा मंगा ली जायेगी। पूर्ण क्रियाशील का तात्पर्य है कि सम्बन्धित एफ०पी०ओ० की आर०ओ०सी० के साथ-साथ आयकर एवं अन्य विधिक औपचारिकताएँ पूर्ण हों तथा उनके व्यवसायिक कार्यक्रम एफ०पी०ओ० की मूल अवधारणा के अनुसार संचालित हों।

3.2.8 अनुश्रवण एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन :

राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई स्तर पर कार्यक्रम की समवर्ती अनुश्रवण के साथ-साथ यथा आवश्यकता "तीसरे पक्ष की निगरानी में अनुश्रवण" की व्यवस्था के संचालन का समन्वय किया जायेगा। मानिट्रिंग रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक वर्ष प्रदेश स्तर पर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार की घोषणा की जायेगी। यह पुरस्कार स्वामी विवेकानन्द की जयन्ती पर ससमारोह मा० मुख्यमंत्री/मा० कृषि मंत्री द्वारा प्रदान किया जायेगा। इसमें स्मृति चिन्ह, प्रमाण-पत्र

तथा शाल भेंट कर सम्बन्धित निदेशक कृषक को सम्मानित किया जायेगा। इस प्रयास से फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के मध्य उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण का सृजन होगा।

3.2.9 डैश बोर्ड की स्थापना :

राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई के स्तर पर प्रदेश में गठित तथा पूर्ण क्रियाशील फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों का एक डैश बोर्ड स्थापित किया जायेगा। इसमें फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों से जुड़ी समस्त जानकारियों जैसे— निदेशकों एवं शेयर होल्डर्स का विवरण, आर०ओ०सी० से जुड़ी अद्यतन रिपोर्ट, बैलेन्स शीट, बैंक खाते का विवरण तथा कम्पनी के व्यावसायिक क्रियाकलापों की रिपोर्ट दर्ज होगी। साथ ही इस पर एक लिंक भी उपलब्ध होगा जिस पर डैश बोर्ड में शामिल कोई भी एफ०पी०ओ० अपने व्यवसाय से जुड़ी अद्यतन जानकारी आन—लाइन भेज सकेगा। एफ०पी०ओ० द्वारा भेजी गयी जानकारी को राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा इसे डैश बोर्ड में सम्बन्धित एफ०पी०ओ० की विवरणिका में दर्ज कर देगा। इस जानकारी के आधार पर फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के व्यावसायिक क्रियाकलापों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने में राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई को आसानी होगी।

4.0 जिला स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई :

एफ०पी०ओ० कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु कृषि विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या—58/2020/2021/12-2-2020-1/2019 दिनांक 4 नवम्बर, 2020 (सपटित कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2020/2133/12-2-2020-1/2019 दिनांक 27 नवम्बर, 2020) द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन निम्नानुसार किया जा चुका है:-

क्र०सं०	नाम	पद
1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	उप कृषि निदेशक	संयोजक/सदस्य सचिव
3.	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
4.	जिला उद्यान अधिकारी	सदस्य
5.	सहायक निदेशक, मत्स्य/रेशम अधिकारी	सदस्य
6.	मण्डी सचिव	सदस्य
7.	जिला प्रबंधक, नाबार्ड	सदस्य
8.	तीन विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केन्द्र, आत्मा स्थानीय उत्पादक संगठन	सदस्य
9.	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य

इस समिति द्वारा जनपद स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु नीतिगत निर्णय लिए जायेंगे। कार्यक्रम के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित जनपद के उप निदेशक कृषि के प्रत्यक्ष संरक्षण/नियंत्रण में एक जनपद स्तरीय एफ०पी०ओ० क्रियान्वयन सेल का औपचारिक गठन किया जायेगा। इस सेल द्वारा विकास खण्ड स्तर पर एफ०पी०ओ० के गठन हेतु किये जा रहे प्रयासों की संकलित जानकारी रखी जायेगी। इस सेल के प्रभारी द्वारा यथा आवश्यकता सम्बन्धित विवरण जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के साथ-साथ जनपद के क्रेडिट—लिन्कड—पोटेन्शियल एग्रीक्लचर डवलपमेंट प्लान तैयार करने हेतु उपयोग में लाया जायेगा। इस प्रयास से जनपद में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का प्रदेश की अर्थव्यवस्था की पर्यावरण अनुकूल परिस्थितियों में प्रदेश में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का अनुशासित उपयोग करते हुये सतत विकास की परिकल्पना को मूर्त रूप प्रदान किया जाना आसान हो जायेगा। जनपद स्तर

पर एफ0पी0ओ0 क्रियान्वयन सेल का मुख्यालय कृषि प्रौद्योगिकीय प्रबन्धन एजेंसी (आत्मा) के जनपद स्तरीय कार्यालय में ही होगा। किस ब्लाक में किस प्रकार का एफ0पी0ओ0 यथा कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम इत्यादि से संबंधित एफ0पी0ओ0 का गठन किया जायेगा। इस संबंध में भी संबंधित विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देश निर्गत किये जायेंगे। जनपद स्तरीय एफ0पी0ओ0 क्रियान्वयन सेल का संगठनात्मक ढाँचा उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 29 सितम्बर, 2020 के अनुसार होगा।

4.1 जनपद एवं विकास खण्ड स्तर के अधिकारियों की कृषक उत्पादक संगठनों की स्थापना में भूमिका :

प्रदेश में कृषि विकास में एफ0पी0ओ0 की अहम भूमिका के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि विभागीय कार्यकलापों में भी एफ0पी0ओ0 सम्बन्धी कार्यों को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी। इन कार्यों को सुचारु रूप से कार्यान्वित करने के लिये जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों के दायित्व निम्नानुसार होंगे—

4.1.1. **मुख्य विकास अधिकारी**— विभिन्न विभागीय योजनाओं से आवश्यक कन्वर्जेंस प्राप्त करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अन्य विभागों की किसानोपयोगी परियोजनाओं में एफ0पी0ओ0 को समाहित करने हेतु आवश्यक समन्वय प्रदान किया जायेगा।

4.1.2 **कृषि विभाग**— कृषि विभाग एफ0पी0ओ0 कार्यक्रम का नोडल विभाग है। अतः इसके प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु विभाग के जनपद स्तरीय एवं विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। तत्कम में बिन्दुवार प्रकार से अधिकारियों की भूमिका एवं उनका दायित्व निम्नवत् है:—

उप निदेशक कृषि — उप निदेशक कृषि द्वारा जनपद स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई की प्रत्येक दो माह में नियमित रूप से बैठक का आयोजन किया जायेगा। उनके द्वारा केन्द्र पोषित योजनाओं में एफ0पी0ओ0 की सहभागिता सुनिश्चित करने के साथ-साथ कृषि विभाग के विकास खण्ड में तैनात कार्मिकों को क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न विभागीय योजनाओं से आवश्यक कन्वर्जेंस प्राप्त करने हेतु मुख्य विकास अधिकारी को यथा आवश्यकता सुझाव प्रदान करेंगे तथा क्रियान्वयन हेतु समयबद्ध आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

जिला कृषि अधिकारी — जिला कृषि अधिकारी द्वारा एफ0पी0ओ0 को उनकी मांग के अनुसार खाद, बीज एवं कीटनाशकों के भण्डारण एवं बिक्री हेतु आवश्यक लाइसेंस निर्गत किया जायेगा। खाद, बीज तथा कीटनाशक रसायनों की जनपद में कमी होने की स्थिति में यथा आवश्यकता उसकी पूर्ति हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा, जिससे एफ0पी0ओ0 से जुड़े किसानों को कोई असुविधा न हो। जिला समिति के निर्देशों के अनुसार एफ0पी0ओ0 के गठन की कार्यवाही में सहयोग प्रदान करेंगे।

सहायक विकास अधिकारी कृषि — विकास खण्ड स्तर पर कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों से एफ0पी0ओ0 को कन्वर्जेंस प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही एवं सहयोग प्रदान करना।

ब्लाक तकनीकी प्रबन्धक (बी0टी0एम0) — ब्लाक तकनीकी प्रबन्धक विकास खण्ड स्तर पर कृषि एवं सहाय्यत क्षेत्र में अद्यतन तकनीकी के उत्पादक समावेश हेतु जनपद स्तरीय आत्मा सेल के निर्देश पर कार्य करता है। इन्हें एफ0पी0ओ0 कार्यक्रम के बारे में अपने विकास खण्ड क्षेत्र के किसानों को जागरूक कर उन्हें संगठित करते हुये एफ0पी0ओ0 से होने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावित उपलब्धियों के बारे में अवगत कराया जायेगा। एफ0पी0ओ0 के पंजीयन

के उपरांत कृषि एवं सहाय्यत क्षेत्र में अद्यतन तकनीकी के समावेश हेतु प्रेरित कर गुणवत्तायुक्त उत्पादकता बढ़ाने में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

सहायक तकनीकी प्रबन्धक (ए0टी0एम0) — ब्लाक तकनीकी प्रबन्धक (बी0टी0एम0) की देखरेख में सम्बन्धित विकास खण्ड में एफ0पी0ओ0 कार्यक्रम में अद्यतन तकनीकी के समावेश के लिए निरन्तर सहयोग प्रदान करना।

- 4.1.3 जिला उद्यान अधिकारी—** जिला उद्यान अधिकारी द्वारा फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी से जुड़े किसानों को उद्यान विभाग द्वारा संचालित विभिन्न औद्यानिक विकास एवं खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करने हेतु आवश्यक समन्वय/कन्वर्जेन्स प्रदान किया जायेगा। जिला समिति के निर्देशों के अनुसार एफ0पी0ओ0 के गठन की कार्यवाही में सहयोग प्रदान करेंगे।
- 4.1.4 मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी —** जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी से जुड़े किसानों को पशुधन विभाग की विभिन्न योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करने हेतु आवश्यक समन्वय/कन्वर्जेन्स प्रदान किया जायेगा। जिला समिति के निर्देशों के अनुसार एफ0पी0ओ0 के गठन की कार्यवाही में सहयोग प्रदान करेंगे।
- 4.1.5 सहायक निदेशक मत्स्य—** जनपद के सहायक निदेशक मत्स्य द्वारा फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी से जुड़े किसानों को मत्स्य विभाग की विभिन्न योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करने हेतु आवश्यक समन्वय/कन्वर्जेन्स प्रदान किया जायेगा। जिला समिति के निर्देशों के अनुसार एफ0पी0ओ0 के गठन की कार्यवाही में सहयोग प्रदान करेंगे।
- 4.1.6 रेशम अधिकारी —** प्रदेश के कुछ जनपदों में रेशम कीट पालन परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सम्बन्धित जनपदों के रेशम अधिकारी द्वारा फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी से जुड़े किसानों को रेशम विभाग की विभिन्न योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करने हेतु आवश्यक समन्वय/कन्वर्जेन्स प्रदान किया जायेगा। जिला समिति के निर्देशों के अनुसार एफ0पी0ओ0 के गठन की कार्यवाही में सहयोग प्रदान करेंगे।
- 4.1.7 मण्डी सचिव —** जनपद की सम्बन्धित मण्डी के सचिव द्वारा वर्तमान कृषि सुधारों के मदेनजर फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी को राष्ट्रीय कृषि विपणन नेटवर्क से जोड़ने हेतु उसका पंजीयन ई—एन0ए0एम0 पोर्टल पर कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त यथा आवश्यकता वर्तमान विपणन व्यवस्था का भी प्रत्यक्ष लाभ फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों को प्रदान करते हुए आर्गेनिक उत्पादों के विपणन हेतु मण्डियों आऊटलेट उपलब्ध कराया जायेगा। जिला समिति के निर्देशों के अनुसार एफ0पी0ओ0 के गठन की कार्यवाही में सहयोग प्रदान करेंगे।
- 4.1.8 जिला खाद्य विपणन अधिकारी —** सम्बन्धित जनपद के जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उपजों के क्रय केन्द्र स्थापना हेतु एफ0पी0ओ0 को अधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा। किसानों की सहायता के लिए कृषि उपज क्रय प्रक्रिया की दुरुहताओं को दूर करने हेतु उनके द्वारा क्रय प्रक्रिया को सघन मॉनिटरिंग की जायेगी।
- 4.1.9 कृषि विज्ञान केन्द्र —** सम्बन्धित जनपद के कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रभारी द्वारा फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों की मांग पर यथा आवश्यकता राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश में मान्य अद्यतन तकनीकी तथा कृषि एवं अन्य सहाय्यत क्षेत्र के उत्पादों की बाजार मांग एवं उसकी प्रस्तावित पूर्ति के तरीके के बारे में आवश्यक जानकारी/प्रशिक्षण प्रदान की जायेगी। साथ ही एफ0पी0ओ0 के सहयोग से कृषि एवं सहाय्यत क्षेत्र के व्यावसायिक प्रदर्शन प्रक्षेत्रों की स्थापना में भी सहयोग प्रदान किया जायेगा। सम्बन्धित कृषि विज्ञान केन्द्र अपनी लिंक कृषि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् छात्रों का आन—फार्म प्रशिक्षण के साथ—साथ एफ0पी0ओ0 से

जुड़े किसानों को भी विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले कृषि तकनीकी विस्तार कार्यक्रम से सीधे जोड़ेंगे।

4.1.10 क्षेत्रीय परिषद —नमामि गंगे परियोजना : नमामि गंगे परियोजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय स्तर पर किसानों को जागरूक/प्रशिक्षित कर कृषक समूह गठित किये जायेंगे। इन गठित कृषक समूहों को राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई के समन्वय से एफ0पी0ओ0 के स्वरूप में स्थापित करने का कार्य किया जायेगा।

उपरोक्त के अलावा प्रस्तर-3.2.4 पर वर्णित अन्य विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी भी एफ0पी0ओ0 कार्यक्रम को सतृप्त रूप से क्रियाशील बनाये रखने हेतु अपना योगदान करेंगे।

कृषि विभाग द्वारा प्रत्येक विकास खण्ड में ए0टी0एम0 तथा बी0टी0एम0 की तैनाती पूर्व से ही है। समस्त कार्मिक कृषि विज्ञान में शिक्षित तथा प्रशिक्षित होते हैं। इन कार्मिकों को एफ0पी0ओ0 कार्यक्रम का प्राथमिक प्रशिक्षण प्रदान कर एफ0पी0ओ0 के गठन कार्यक्रम की प्राथमिक कड़ी के रूप में उपयोग में लाया जायेगा। फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के पंजीयन की कार्यवाही राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई के समन्वय से समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर जी जायेगी।

5.0 प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन :

5.1 प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम :

किसी भी नये कार्यक्रम के सफल एवं समयबद्ध संचालन हेतु पूर्ण रूप से प्रशिक्षित कार्यदल की नितान्त आवश्यकता होती है। इसके लिए राज्य स्तरीय इकाई द्वारा एक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार किया जायेगा जिसके क्रम में कृषि विभाग के मण्डल स्तरीय, जनपद स्तरीय एवं खण्ड विकास स्तरीय अधिकारियों का अलग-अलग बैचों में व्यावहारिक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इसके अन्तर्गत प्रत्येक जनपद के 02 ए0टी0एम0/बी0टी0एम0 तथा 02 अग्रणी किसानों को फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के गठन तथा उसके सफल संचालन का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इन प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा अपने जनपदों में कार्यक्रम से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े विभागीय कार्मिकों/अन्य किसानों को जानकारी प्रदान कर उन्हें एफ0पी0ओ0 गठन हेतु प्रेरित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा। इसका आयोजन वर्तमान में कोविड प्रोटोकाल को देखते हुए वर्चुवल तरीके से एन0आई0सी0 नेटवर्क के माध्यम से किया जायेगा। यथा आवश्यकता भविष्य में यह आयोजन कृषि विभाग के राज्य स्तरीय कृषि प्रशिक्षण संस्थान, रहमान खेड़ा, लखनऊ में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपरान्त प्रशिक्षित किसानों/विभागीय कार्मिकों के सहयोग प्रस्तर-3.2.2 पर अंकित विवरण के अनुसार फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के गठन में प्रत्यक्ष सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

5.2 कम्पनी के निदेशकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम :

फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के गठन के तीन माह की अवधि के अन्दर प्रत्येक फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी से दो निदेशकों का कम्पनी के रख-रखाव तथा कृषि एवं सहाय्यत क्षेत्र के कार्यक्रमों से जुड़े मूल्य श्रृंखला स्थापना करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण सम्बन्धित विषय वस्तु विशेषज्ञों द्वारा प्रदान किया जायेगा। यह प्रशिक्षण राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ में प्रदान किया जायेगा। प्रत्येक बैच में 25 किसान निदेशक सम्मिलित होंगे। प्रशिक्षण के दौरान लखनऊ तथा उसके आस-पास के जनपदों में पूर्व से कार्यरत एवं सफल फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के प्रक्षेत्रों का भ्रमण भी कराया जायेगा जिससे “किसानों द्वारा किसानों का प्रशिक्षण सत्र” भी स्वतः पूर्ण हो जायेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कैलेंडर प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में ही राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा जारी कर दिया जायेगा। प्रशिक्षण शिड्यूल संलग्नक-02 पर प्रस्तुत है।

5.3 कम्पनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों का कम्पनी प्रबन्धन एवं लेखा रखाव हेतु व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम :

राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज तथा इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स आफ इण्डिया के सहयोग से फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के व्यावहारिक प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम तैयार लिया गया है। प्रशिक्षण शिड्यूल संलग्नक-3 पर प्रस्तुत है। उन्हें विभिन्न बैचों (25 प्रशिक्षार्थी/बैच) में तीन दिन अवधि का प्रशिक्षण राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ में प्रदान किया जायेगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारियों का प्रशिक्षण 03 दिवसीय कार्य अन्तराल का होगा जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी से जुड़े लेखा सम्बन्धी कार्यों का रख-रखाव, रजिस्ट्रार आफ कम्पनी की विधिक बाध्यताओं के आलोक में आवश्यक प्रपत्रों को तैयार कर उसे आन लाइन जमा करना, कम्पनी की वर्तमान कार्य योजना का समुचित प्रबन्धन तथा उसके भविष्य की कार्य योजना को समय से तैयार करना, बैंकिंग लेन-देन तथा शेयर होल्डर्स के साथ समयबद्ध भौतिक तथा वर्चुवल सम्वाद करना इत्यादि सम्मिलित होगा। प्रशिक्षण के दौरान मुख्य कार्यपालक अधिकारियों का प्रदेश स्तर/राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे कार्य कर रहे फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों को यथा आवश्यकता भ्रमण भी कराया जायेगा।

राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान में आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन अलग-अलग बैचों में किया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक बैच में अधिकतम 25 प्रशिक्षार्थी सम्मिलित होंगे। इसके अतिरिक्त समय-समय पर वेबिनार का आयोजन कर फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के निदेशको एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को सम्बन्धित विषयों की अद्यतन जानकारी भी राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कैलेंडर प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में ही राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा जारी कर दिया जायेगा।

6.0 फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के गठन हेतु राज्य स्तरीय उत्प्रेरकों के पैनल का गठन :

राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा प्रदेश स्तर पर एफ0पी0ओ0 गठन हेतु अनुभवी एवं विषय वस्तु विशेषज्ञ स्वैच्छिक उत्प्रेरकों का एक पैनल गठित किया जायेगा। इस पैनल में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में गठित एवं क्रियाशील ऐसी फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के प्रथम निदेशक सम्मिलित किये जायेंगे जिनके द्वारा कृषि उत्पाद मूल्य श्रृंखला संवर्धन हेतु कम से कम 02 दो वर्षों से कार्य किया जा रहा हो तथा कम्पनी का वार्षिक टर्न-ओवर रू0 50.00 लाख से अधिक हो।

इस पैनल में सम्मिलित स्वैच्छिक विशेषज्ञों की अधिकतम संख्या 50 होगी। इन विशेषज्ञों द्वारा अपने क्षेत्र में किसानों को उत्प्रेरित कर कृषि उत्पाद मूल्य श्रृंखला संवर्धन तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं से कन्वर्जेंस सहायता प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया जायेगा। साथ ही अपने निकटवर्ती विकासखण्ड के जागरूक किसानों को प्रशिक्षित/उत्प्रेरित कर फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के गठन में भी सहयोग प्रदान किया जायेगा। इन विशेषज्ञों को राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई के अनुमोदनोंपरान्त उनकी सेवाओं के लिए नियमानुसार मानदेय प्रदान करने की व्यवस्था की जायेगी, जो एफ0पी0ओ0 के सफलतापूर्वक गठन के उपरान्त देय होगा। पैनल में सम्मिलित स्वैच्छिक विशेषज्ञों को उनकी स्वैच्छिक सेवाओं हेतु राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा पहचान पत्र भी प्रदान किया जायेगा। एफ0पी0ओ0 उत्प्रेरक किसी भी राजनीतिक संगठन सक्रिय सदस्य नहीं होगा।

7.0 प्रस्तावित लक्ष्य:- उ0प्र0 कृषक उत्पादक संगठन नीति-2020 के अनुपालन हेतु निर्गत क्रियान्वयन दिशा-निर्देश लागू होने के उपरान्त प्रस्तावित लक्ष्य निम्नवत् हैं:-

वर्ष	फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों की सं०	कुल प्रत्यक्ष लाभान्वित किसान/शेयर होल्डर	अनुमानित पर्यावरण अनुकूल कृषि एवं सहाय्यित क्षेत्र क्रियाकलापों के कारण उत्पादक क्षेत्रफल में वृद्धि (एकड़ में)	कृषि एवं सहाय्यित क्षेत्र क्रियाकलापों तथा मूल्य सवर्धन श्रृंखला उत्पादन के कारण कुल अनुमानित वार्षिक उत्पादन (करोड़ रुपये में)
2020-21 का शेष भाग	800	04.00 लाख	5.00 लाख	12000.00
2021-22	1600	08.00 लाख	10.00 लाख	25000.00
2022-23	1600	08.00 लाख	10.00 लाख	25000.00
योग	4000	20.00 लाख	25.00 लाख	62000.00

उक्त प्रस्तावित उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई तथा जनपद स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई मिशन मोड में कार्य का निस्तारण करेंगी। दोनों ही स्तर पर कोविड-19 महामारी काल के दौरान भारत सरकार द्वारा कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र के सत्त विकास हेतु घोषित एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फण्ड तथा इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फण्ड के अन्तर्गत घोषित परियोजनाओं के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों/शासनादेशों से आबद्ध होकर कन्वर्जेंस प्राप्त करते हुए परियोजनाओं का "वैल्यू चेन मेकेनिज्म" के अन्तर्गत उद्यमिता मोड में क्रियान्वित किया जायेगा। उत्पाद मूल्य श्रृंखला स्थापना हेतु प्रदेश स्तर पर विभिन्न व्यावसायिक बैंकों तथा डेवलपमेंट फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्स से राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई स्तर पर आवश्यक समन्वय किया जायेगा, जिससे जनपद स्तर पर फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के निदेशकों को आवश्यक बैंकिंग सुविधाएं सहजता से उपलब्ध हो सकें। यथा आवश्यकता जनपदों के कृषि आधारित पोर्टेन्शियल लिंकड क्रेडिट प्लान बनाते समय सम्बन्धित जनपद की जनपद स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा सम्बन्धित जनपद में कार्यरत समस्त फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों से उनकी कार्य योजना लेकर निश्चित रूप से संकलित करा लेनी होगी।

----- / / -----

MEMORANDUM

AND

ARTICLES

OF

ASSOCIATION

OF

.....

.....

THE COMPANIES ACT, 2013
(Company limited by shares)
Memorandum of Association
of

.....

1. The name of the company is "CUTRUNN CREATION PRIVATE LIMITED"
2. The Registered office of the Company will be situated in the **STATE OF UTTAR PRADESH.**
3. (a) The objects to be pursued by the company on its incorporation are:—

Agriculture and Plantation activity

1. To provide the necessary infrastructure to harvest and develop forest resources based, to promote forest resources based Industries, to arrange marketing of timber and other forest resources on the mainland and abroad.
2. To plant, grow, cultivate, produce, and raise plantations of various forest species of proven utility and other agricultural, plantation, horticultural crops, medicinal and aromatic plants and to buy, sell, export, import, process, distribute, or otherwise deal with all kinds of forest crops, natural products agricultural, plantation and horticultural crops, medicinal and aromatic plants.
3. To carry on the business of planters, cultivators, producers, sellers and dealers in timber, processed or not and such other products of every description and to manufacture, dispose of sell and deal in products of natural forest and forest plantations, agricultural, plantation and horticultural crops and medicinal and aromatic plants.
4. To establish, administer, own and run industries for manufacturing forest products, agricultural, plantation and horticultural products, medicinal and aromatic plants.
5. To conduct and contract for training and research connected with the integrated development of forest resources of the islands and cultivation as well as processing of agricultural, plantation and horticultural crops, medicinal and aromatic plants.
6. To maintain and improve Wild Life and other natural Resources.

(b) Matters which are necessary for furtherance of the objects specified in clause 3(a) are:—

1. To buy all kinds of plant, equipment, machinery, apparatus, tools, utensils, commodities, substances, articles and things necessary or useful for carrying on the objects of the Company.

2. To enter into agreement with any company or persons for obtaining by grant of license or on such other terms of all types, formulae and such other rights and benefits, technical information, know-how and expert guidance and equipment and machinery and things mentioned herein above and to arrange facilities for training of technical personnel by them.
3. To establish, provide, maintain and conduct or otherwise, subsidized research laboratories and experimental workshops for scientific and technical research and experiments and to undertake and carry on with all scientific and technical research, experiments and tests of all kinds and to promote studies and research both scientific and technical investigation and invention by providing, subsidizing, endowing or assisting laboratories, workshops, libraries, lectures, meetings and conferences and by providing the remuneration to scientific and technical professors and teachers and to award, scholarships, prizes, grants and bursaries to students and to encourage, promote and reward studies, researches, investigations, experiments, tests and inventions of any kind that may be considered likely to assist the objects of the Company.
4. To acquire by concession, grant, purchase, license or otherwise either absolutely or conditionally and either alone or jointly with others land, buildings, machinery, plants, utensils, works, conveniences and such other movable and immovable properties of any description and any patents, trademarks, concessions, privileges, brevets, d'invention, licenses, protections and concessions conferring any exclusive or limited rights to any inventions, information which may seem necessary for any of the objects of the Company and to construct, maintain and alter any building or work, necessary or convenient for the business of the Company and to pay for such land, buildings, works, property or rights or any such other property and rights purchased or acquired by or for the Company by shares, debentures, debenture stock, bonds or such other securities of the Company or otherwise and manage, develop or otherwise dispose of in such manner and for such consideration as may be deemed proper or expedient to attain the main objects of the Company.
5. Subject to the provisions of the Companies Act, 2013 to amalgamate with any other Company having objects altogether or in part similar to those of this Company.
6. To enter into any arrangement with any Government or Authorities Municipal, local or otherwise or any person or company in India or abroad, that may seem conducive to the objects of the company or any of them and to obtain from any such Government, Authority persons or company any rights, privileges, charters, contracts, licenses and concessions including in particular rights in respect of waterways, roads and highways, which the Company may carry out, exercise and comply therewith.

7. To apply for and obtain any order of Central/State or such other Authority for enabling the Company to carry on any of its objects into effect or for effecting any modifications of the Company's constitution or any other such purpose, which may seem expedient and to make representations against any proceedings or applications which may seem calculated directly or indirectly to prejudice the company's interests.
8. To enter into partnership or into any arrangement for sharing profits, union of interests, co-operation, joint-venture, reciprocal concessions or otherwise with any person, or company carrying on or engaged in any business or transaction which this Company is authorized to carry on.
9. To purchase or otherwise acquire and undertake the whole or any part of the business, property, rights and liabilities of any company, firms or person carrying on business which this Company is authorized to carry on or is possessed of rights suitable for the objects of this Company.
10. To do all or any of the above things as principals, agents, contractors, trustees or otherwise and by or through trustees, agents or otherwise and either alone or in conjunction with others and to do all such other things as are incidental or as may be conducive to the attainment of the objects or any of them.
11. To promote, form and register, aid in the promotion, formation and registration of any company or companies, subsidiary or otherwise for the purpose of acquiring

all or any of the properties, rights and liabilities of this Company and to transfer to any such company any property of this company and to be interested in or take or otherwise acquire, hold, sell or otherwise dispose of shares, stock, debentures and such other securities of all types in or of any such company, subsidiary or otherwise for all or any of the objects mentioned in this Memorandum of Association and to assist any such company and to undertake the management and secretarial or such other work, duties and business on such terms as may be arranged.

12. To open accounts with any bank or financial institution and to draw make, accept, endorse, discount, execute and issue promissory notes, bills of exchange, hundies, bills of lading, warrants, debentures and such other negotiable or transferable instruments of all types and to buy the same.
13. Subject to the provisions of the Companies Act, 2013 including the rules and regulations made therein and the directions issued by Reserve Bank of India to borrow, raise or secure the payment of money or to receive money as loan, at interest for any of the objects of the company and at such time or times as may be expedient, by promissory notes, bills of exchange, hundies, bills of lading, warrants or such other negotiable instruments of all types or by taking

credit in or opening current accounts or over-draft accounts with any person, firm, bank or company and whether with or without any security or by such other means, as may deem expedient and in particular by the issue of debentures or debenture stock, perpetual or otherwise and in security for any such money so borrowed, raised or received and of any such debentures or debenture stock so issued, to mortgage, pledge or charge the whole or any part of the property and assets of the Company both present and future, including its uncalled capital, by special assignment or otherwise or to transfer or convey the same absolutely or in trust and to give the lenders power of sale and other powers as may seem expedient and to purchase, redeem or pay off such securities provided that the Company shall not carry on the business of banking within the meaning of the Banking Regulation Act, 1949.

14. To advance money not immediately required by the Company or give credit to such persons, firms or companies and on such terms with or without security as may seem expedient and in particular to customers of and such others having dealings with the Company and to give guarantees or securities of any such persons, firms, companies as may appear proper or reasonable provided that the Company shall not carry on the business of banking, within the meaning of Banking Regulation Act, 1949.
15. To improve alter, manage, develop, exchange, mortgage, enfranchise and dispose of, any part of the land, properties, assets and rights and the resources and undertakings of the Company, in such manner and on such terms as the Company may determine.
16. To remunerate any person or company, for services rendered or to be rendered in or about the formation or promotion of the Company or the conduct of its business, subject to the provisions of the Companies Act, 2013.
17. To create any depreciation fund, reserve fund, sinking fund, provident fund, superannuation fund or any other such special fund, whether for depreciations, repairing, improving, extending or maintaining any of the properties and assets of the Company or for redemption of debentures or redeemable preference shares, worker's welfare or for any other such purpose conducive to the interest of the Company.
18. To provide for the welfare of employees or ex-employees (including Directors and other officers) of the Company and the wives and families or the dependents or connections of such persons, by building or contributing to the building of houses, or dwellings or chawls or by grants of money, pensions, allowances, bonus or other such payments or be creating and from time to time, subscribing or contributing to provident fund and other associations, institutions, funds or trusts, and/or by providing or subscribing or contributing towards places of instruction and recreation, hospitals and dispensaries, medical and such other attendances and assistance as the Company shall determine.

19. To undertake and execute any trusts, the undertaking of which may seem desirable, either gratuitously or otherwise, for the attainment of the main objects of the Company.
 20. To procure the incorporation, registration or such other recognition of the Company in the Country, State or place outside India and to establish and maintain local registers and branch places of the main business in any part of the world.
 21. To adopt such means of making known the business of the Company as may seem expedient and in particular by advertising over the internet or any other electronic media and also in print media in the press by circulars, by purchase and exhibition of works of art or interest, by publication of books and periodicals and by granting prizes, rewards or organizing exhibitions.
 22. The company would obtain approval of the concerned authorities to carry on the objects of the company and the matters which are necessary for furtherance of the objects of the Company as given in this memorandum of association wherever required.
-
4. The liability of the member(s) is limited and this liability is limited to the amount unpaid, if any, on the shares held by them.
 5. The Authorised Share Capital of the company is Rs.1000000/- (Rupees Ten Lac Only.) divided into 100000 (One Lac Only.) shares of Rs.10/- (Rupees Ten Only.) each.

THE COMPANIES ACT, 2013
(Company limited by shares)
ARTICLES OF ASSOCIATION
OF

Preliminary	1	Subject as hereinafter provided the Regulations contained in Table 'A' in the First Schedule to the Companies Act, shall apply to the Company except in so far as otherwise expressly incorporated herein below
Interpretation	2	<p>Unless the context otherwise requires, words or expressions contained in these regulations shall bear the same meaning as in the Act or any statutory modification thereof in force at the date at which these regulations become binding on the company.</p> <p>"The Act" means the Companies Act, 2013</p> <p>"These Articles" means these Articles of Association as originally framed or as altered by Special Resolution, from time to time.</p> <p>"The company" means CUTRUNN CREATION PRIVATE LIMITED Ltd.</p> <p>"The office" means the Registered office for the time being of the company.</p> <p>"The Register" means the Register of members to be kept pursuant to section 88 of the Act.</p> <p>"The Board" means the board of Directors of the company.</p> <p>"Dividend" includes bonus.</p> <p>"Month" means Calendar month.</p> <p>"Year" means a calendar year and "Financial year" shall have the meaning assigned thereto by Section 2(41) of the Act.</p> <p>"Seal" means the common Seal of the Company.</p> <p>"The Directors" means the Directors for the time being of the company. Provided that following shall be the first Directors</p>

of the company.

Private Company	3	<p>"Private Company" "private company" means a company having a minimum paid-up share capital of one lakh rupees or such higher paid-up share capital as may be prescribed, and which by its articles,—</p> <p>(i) restricts the right to transfer its shares;</p> <p>(ii) except in case of One Person Company, limits the number of its members to two hundred:</p> <p>Provided that where two or more persons hold one or more shares in a company jointly, they shall, for the purposes of this clause, be treated as a single member:</p> <p>Provided further that—</p> <p>(A) persons who are in the employment of the company; and</p> <p>(B) persons who, having been formerly in the employment of the company, were members of the company while in that employment and have continued to be members after the employment ceased, shall not be included in the number of members; and</p> <p>(iii) prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities of the company;</p>
Table "A" not to Apply	4	<p>Save as Provided herein , the Regulations contained in Table "A" in Schedule 1 of the Act shall not apply to Company.</p>
Share Capital	5	<p>The authorized share capital of the company shall be as stated in clauses V of the memorandum of Association of the company. The company has power to divide the share capital for the time being into several classes and to increase or reduce its capital from time to time and vary, modify or abrogate rights or conditions attached to any class of the shares in such manner as may be for the time being provided by regulations of the company and upon increase of the capital the company may issue new shares in priority to any other share present and future with any preferential, deferred, qualified or special privileges or conditions as may be determined upon by the company in the General Meeting</p>
	5.1	<p>The Business of the Company may be commenced soon after the incorporation of the company as and when the directors shall think fit notwithstanding that part of the shares have been allotted.</p>
Share capital and variation of rights	6.1	<p>Subject to the provisions of the Act and these Articles, the shares in the capital of the company shall be under the control of the Directors who may issue, allot or otherwise dispose of the same or any of them to such persons, in such proportion and on such terms and conditions and either at a</p>

premium or at par and at such time as they may from time to time think fit.

- 6.2 (i) Every person whose name is entered as a member in the register of members shall be entitled to receive within two months after incorporation, in case of subscribers to the memorandum or after allotment or within one month after the application for the registration of transfer or transmission or within such other period as the conditions of issue shall be provided,—

(a) one certificate for all his shares without payment of any charges; or

(b) several certificates, each for one or more of his shares, upon payment of twenty rupees for each certificate after the first.

(ii) Every certificate shall be under the seal and shall specify the shares to which it relates and the amount paid-up thereon.

(iii) In respect of any share or shares held jointly by several persons, the company shall not be bound to issue more than one certificate, and delivery of a certificate for a share to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all such holders.

- 6.3 (i) If any share certificate be worn out, defaced, mutilated or torn or if there be no further space on the back for endorsement of transfer, then upon production and surrender thereof to the company, a new certificate may be issued in lieu thereof, and if any certificate is lost or destroyed then upon proof thereof to the satisfaction of the company and on execution of such indemnity as the company deem adequate, a new certificate in lieu thereof shall be given. Every certificate under this Article shall be issued on payment of twenty rupees for each certificate.

(ii) The provisions of Articles (2) and (3) shall *mutatis mutandis* apply to debentures of the company.

- 6.4 Except as required by law, no person shall be recognised by the company as holding any share upon any trust, and the company shall not be bound by, or be compelled in any way to recognise (even when having notice thereof) any equitable, contingent, future or partial interest in any share, or any interest in any fractional part of a share, or (except only as by these regulations or by law otherwise provided) any other rights in respect of any share except an absolute right to the

entirety thereof in the registered holder.

- 6.5 (i) The company may exercise the powers of paying commissions conferred by sub-section (6) of section 40, provided that the rate per cent. or the amount of the commission paid or agreed to be paid shall be disclosed in the manner required by that section and rules made thereunder.

(ii) The rate or amount of the commission shall not exceed the rate or amount prescribed in rules made under sub-section (6) of section 40.

(iii) The commission may be satisfied by the payment of cash or the allotment of fully or partly paid shares or partly in the one way and partly in the other.

- 6.6 (i) If at any time the share capital is divided into different classes of shares, the rights attached to any class (unless otherwise provided by the terms of issue of the shares of that class) may, subject to the provisions of section 48, and whether or not the company is being wound up, be varied with the consent in writing of the holders of three-fourths of the issued shares of that class, or with the sanction of a special resolution passed at a separate meeting of the holders of the shares of that class.

(ii) To every such separate meeting, the provisions of these regulations relating to general meetings shall *mutatis mutandis* apply, but so that the necessary quorum shall be at least two persons holding at least one-third of the issued shares of the class in question.

- 6.7 The rights conferred upon the holders of the shares of any class issued with preferred or other rights shall not, unless otherwise expressly provided by the terms of issue of the shares of that class, be deemed to be varied by the creation or issue of further shares ranking *pari passu* therewith

- 6.8 Subject to the provisions of section 55, any preference shares may, with the sanction of an ordinary resolution, be issued on the terms that they are to be redeemed on such terms and in such manner as the company before the issue of the shares may, by special resolution, determine.

Lien

- 7 (i) The company shall have a first and paramount lien—

(a) on every share (not being a fully paid share), for all

monies (whether presently payable or not) called, or payable at a fixed time, in respect of that share; and

(b) on all shares (not being fully paid shares) standing registered in the name of a single person, for all monies presently payable by him or his estate to the company:

Provided that the Board of directors may at any time declare any share to be wholly or in part exempt from the provisions of this clause.

(ii) The company's lien, if any, on a share shall extend to all dividends payable and bonuses declared from time to time in respect of such shares.

7.1 (i) To give effect to any such sale, the Board may authorise some person to transfer the shares sold to the purchaser thereof.

(ii) The purchaser shall be registered as the holder of the shares comprised in any such transfer.

(iii) The purchaser shall not be bound to see to the application of the purchase money, nor shall his title to the shares be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the sale.

7.2 (i) The proceeds of the sale shall be received by the company and applied in payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable.

(ii) The residue, if any, shall, subject to a like lien for sums not presently payable as existed upon the shares before the sale, be paid to the person entitled to the shares at the date of the sale.

Calls on shares

8 (i) The Board may, from time to time, make calls upon the members in respect of any monies unpaid on their shares (whether on account of the nominal value of the shares or by way of premium) and not by the conditions of allotment thereof made payable at fixed times:

Provided that no call shall exceed one-fourth of the nominal value of the share or be payable at less than one month from the date fixed for the payment of the last preceding call.

(ii) Each member shall, subject to receiving at least fourteen days' notice specifying the time or times and place of payment, pay to the company, at the time or times and place so specified, the amount called on his shares.

(iii) A call may be revoked or postponed at the discretion of the Board.

8.1 A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the Board authorizing the call was passed and may be required to be paid by installments.

8.2 The joint holders of a share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect thereof.

8.3 (i) If a sum called in respect of a share is not paid before or on the day appointed for payment thereof, the person from whom the sum is due shall pay interest thereon from the day appointed for payment thereof to the time of actual payment at ten per cent. per annum or at such lower rate, if any, as the Board may determine.

(ii) The Board shall be at liberty to waive payment of any such interest wholly or in part.

8.4 (i) Any sum which by the terms of issue of a share becomes payable on allotment or at any fixed date, whether on account of the nominal value of the share or by way of premium, shall, for the purposes of these regulations, be deemed to be a call duly made and payable on the date on which by the terms of issue such sum becomes payable.

(ii) In case of non-payment of such sum, all the relevant provisions of these regulations as to payment of interest and expenses, forfeiture or otherwise shall apply as if such sum had become payable by virtue of a call duly made and notified.

8.5 The Board—

(a) may, if it thinks fit, receive from any member willing to advance the same, all or any part of the monies uncalled and unpaid upon any shares held by him; and

(b) upon all or any of the monies so advanced, may (until the same would, but for such advance, become presently payable) pay interest at such rate not exceeding, unless the company in general meeting shall otherwise direct, twelve per cent. per annum, as may be agreed upon between the Board and the member paying the sum in advance.

Transfer of shares

9 (i) The instrument of transfer of any share in the company shall be executed by or on behalf of both the transferor and transferee.

(ii) The transferor shall be deemed to remain a holder of the share until the name of the transferee is entered in the register of members in respect thereof.

9.1 The Board may, subject to the right of appeal conferred by section 58 decline to register—

(a) the transfer of a share, not being a fully paid share, to a person of whom they do not approve; or

(b) any transfer of shares on which the company has a lien.

9.2 The Board may decline to recognise any instrument of transfer unless—

(a) the instrument of transfer is in the form as prescribed in rules made under sub-section (1) of section 56;

(b) the instrument of transfer is accompanied by the certificate of the shares to which it relates, and such other evidence as the Board may reasonably require to show the right of the transferor to make the transfer; and

(c) the instrument of transfer is in respect of only one class of shares.

9.3 On giving not less than seven days' previous notice in accordance with section 91 and rules made thereunder, the registration of transfers may be suspended at such times and for such periods as the Board may from time to time determine:

Provided that such registration shall not be suspended for more than thirty days at any one time or for more than forty-five days in the aggregate in any year.

9.4 (i) On the death of a member, the survivor or survivors where the member was a joint holder, and his nominee or nominees or legal representatives where he was a sole holder, shall be the only persons recognised by the company as having any title to his interest in the shares.

(ii) Nothing in clause (i) shall release the estate of a deceased joint holder from any liability in respect of any share which had been jointly held by him with other persons.

9.5 (i) Any person becoming entitled to a share in consequence of the death or insolvency of a member may, upon such evidence being produced as may from time to time properly be required by the Board and subject as hereinafter provided, elect, either—

(a) to be registered himself as holder of the share; or

(b) to make such transfer of the share as the deceased or insolvent member could have made.

(ii) The Board shall, in either case, have the same right to decline or suspend registration as it would have had, if the deceased or insolvent member had transferred the share before his death or insolvency.

9.6 (i) If the person so becoming entitled shall elect to be registered as holder of the share himself, he shall deliver or send to the company a notice in writing signed by him stating that he so elects.

(ii) If the person aforesaid shall elect to transfer the share, he shall testify his election by executing a transfer of the share.

(iii) All the limitations, restrictions and provisions of these regulations relating to the right to transfer and the registration of transfers of shares shall be applicable to any such notice or transfer as aforesaid as if the death or insolvency of the member had not occurred and the notice or transfer were a transfer signed by that member.

9.7 A person becoming entitled to a share by reason of the death or insolvency of the holder shall be entitled to the same dividends and other advantages to which he would be entitled if he were the registered holder of the share, except that he shall not, before being registered as a member in respect of the share, be entitled in respect of it to exercise any right conferred by membership in relation to meetings of the company:

Provided that the Board may, at any time, give notice requiring any such person to elect either to be registered himself or to transfer the share, and if the notice is not complied with within ninety days, the Board may thereafter withhold payment of all dividends, bonuses or other monies payable in respect of the share, until the requirements of the notice have been complied with.

9.8 In case of a One Person Company—

(i) on the death of the sole member, the person nominated by such member shall be the person recognized by the company as having title to all the shares of the member;

(ii) the nominee on becoming entitled to such shares in case of the member's death shall be informed of such event by the Board of the company;

(iii) such nominee shall be entitled to the same dividends and

other rights and liabilities to which such sole member of the company was entitled or liable;

(iv) on becoming member, such nominee shall nominate any other person with the prior written consent of such person who, shall in the event of the death of the member, become the member of the company.

Forfeiture of shares 10

If a member fails to pay any call, or installment of a call, on the day appointed for payment thereof, the Board may, at any time thereafter during such time as any part of the call or installment remains unpaid, serve a notice on him requiring payment of so much of the call or installment as is unpaid, together with any interest which may have accrued.

10.1 The notice aforesaid shall—

(a) name a further day (not being earlier than the expiry of fourteen days from the date of service of the notice) on or before which the payment required by the notice is to be made; and

(b) state that, in the event of non-payment on or before the day so named, the shares in respect of which the call was made shall be liable to be forfeited.

10.2 If the requirements of any such notice as aforesaid are not complied with, any share in respect of which the notice has been given may, at any time thereafter, before the payment required by the notice has been made, be forfeited by a resolution of the Board to that effect.

10.3 (i) A forfeited share may be sold or otherwise disposed of on such terms and in such manner as the Board thinks fit.

(ii) At any time before a sale or disposal as aforesaid, the Board may cancel the forfeiture on such terms as it thinks fit.

10.4 (i) A person whose shares have been forfeited shall cease to be a member in respect of the forfeited shares, but shall, notwithstanding the forfeiture, remain liable to pay to the company all monies which, at the date of forfeiture, were presently payable by him to the company in respect of the shares.

(ii) The liability of such person shall cease if and when the company shall have received payment in full of all such monies in respect of the shares.

10.5 (i) A duly verified declaration in writing that the declarant is a director, the manager or the secretary, of the company, and that a share in the company has been duly forfeited on a date

stated in the declaration, shall be conclusive evidence of the facts therein stated as against all persons claiming to be entitled to the share;

(ii) The company may receive the consideration, if any, given for the share on any sale or disposal thereof and may execute a transfer of the share in favour of the person to whom the share is sold or disposed of;

(iii) The transferee shall thereupon be registered as the holder of the share; and

(iv) The transferee shall not be bound to see to the application of the purchase money, if any, nor shall his title to the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sale or disposal of the share.

- 10.6 The provisions of these regulations as to forfeiture shall apply in the case of nonpayment of any sum which, by the terms of issue of a share, becomes payable at a fixed time, whether on account of the nominal value of the share or by way of premium, as if the same had been payable by virtue of a call duly made and notified.

Alteration of capital 11 The company may, from time to time, by ordinary resolution increase the share capital by such sum, to be divided into shares of such amount, as may be specified in the resolution.

- 11.1 Subject to the provisions of section 61, the company may, by ordinary resolution,—

(a) consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares;

(b) convert all or any of its fully paid-up shares into stock, and reconvert that stock into fully paid-up shares of any denomination;

(c) sub-divide its existing shares or any of them into shares of smaller amount than is fixed by the memorandum;

(d) cancel any shares which, at the date of the passing of the resolution, have not been taken or agreed to be taken by any person.

- 11.2 Where shares are converted into stock,—

(a) the holders of stock may transfer the same or any part thereof in the same manner as, and subject to the same regulations under which, the shares from which the stock arose might before the conversion have been transferred, or as near thereto as circumstances admit:

Provided that the Board may, from time to time, fix the minimum amount of stock transferable, so, however, that such minimum shall not exceed the nominal amount of the shares from which the stock arose.

(b) the holders of stock shall, according to the amount of stock held by them, have the same rights, privileges and advantages as regards dividends, voting at meetings of the company, and other matters, as if they held the shares from which the stock arose; but no such privilege or advantage (except participation in the dividends and profits of the company and in the assets on winding up) shall be conferred by an amount of stock which would not, if existing in shares, have conferred that privilege or advantage.

(c) such of the regulations of the company as are applicable to paid-up shares shall apply to stock and the words "share" and "shareholder" in those regulations shall include "stock" and "stock-holder" respectively.

11.3 The company may, by special resolution, reduce in any manner and with, and subject to, any incident authorized and consent required by law,—

- (a) its share capital;
- (b) any capital redemption reserve account; or
- (c) any share premium account.

Capitalisation of profits

12 (i) The company in general meeting may, upon the recommendation of the Board, resolve—

- (a) that it is desirable to capitalise any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the company's reserve accounts, or to the credit of the profit and loss account, or otherwise available for distribution; and
- (b) that such sum be accordingly set free for distribution in the manner specified in clause (ii) amongst the members who would have been entitled thereto, if distributed by way of dividend and in the same proportions.

(ii) The sum aforesaid shall not be paid in cash but shall be applied, subject to the provision contained in clause (iii), either in or towards—

- (A) paying up any amounts for the time being unpaid on any shares held by such members respectively;
- (B) paying up in full, unissued shares of the company to be allotted and distributed, credited as fully paid-up, to and amongst such members in the proportions aforesaid;
- (C) partly in the way specified in sub-clause (A) and partly in that specified in sub-clause (B);
- (D) A securities premium account and a capital redemption reserve account may, for the purposes of this regulation, be

applied in the paying up of unissued shares to be issued to members of the company as fully paid bonus shares;

(E) The Board shall give effect to the resolution passed by the company in pursuance of this regulation.

12.1 (i) Whenever such a resolution as aforesaid shall have been passed, the Board shall—

(a) make all appropriations and applications of the undivided profits resolved to be capitalised thereby, and all allotments and issues of fully paid shares if any; and

(b) generally do all acts and things required to give effect thereto.

(ii) The Board shall have power—

(a) to make such provisions, by the issue of fractional certificates or by payment in cash or otherwise as it thinks fit, for the case of shares becoming distributable in fractions; and

(b) to authorise any person to enter, on behalf of all the members entitled thereto, into an agreement with the company providing for the allotment to them respectively, credited as fully paid-up, of any further shares to which they may be entitled upon such capitalisation, or as the case may require, for the payment by the company on their behalf, by the application thereto of their respective proportions of profits resolved

to be capitalised, of the amount or any part of the amounts remaining unpaid on their existing shares;

(iii) Any agreement made under such authority shall be effective and binding on such members.

Buy-back of shares 13 Notwithstanding anything contained in these articles but subject to the provisions of sections 68 to 70 and any other applicable provision of the Act or any other law for the time being in force, the company may purchase its own shares or other specified securities.

General meetings 14 All general meetings other than annual general meeting shall be called extraordinary general meeting.

14.1 (i) The Board may, whenever it thinks fit, call an extraordinary general meeting.

(ii) If at any time directors capable of acting who are sufficient in number to form a quorum are not within India, any director or any two members of the company may call an extraordinary general meeting in the same manner, as nearly as possible, as that in which such a meeting may be called by the Board.

Proceedings at
general meetings 15 (i) No business shall be transacted at any general meeting unless a quorum of members is present at the time when the meeting proceeds to business.

(ii) Save as otherwise provided herein, the quorum for the general meetings shall be as provided in section 103.

15.1 The chairperson, if any, of the Board shall preside as Chairperson at every general meeting of the company.

15.2 If there is no such Chairperson, or if he is not present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, or is unwilling to act as chairperson of the meeting, the directors present shall elect one of their members to be Chairperson of the meeting.

15.3 If at any meeting no director is willing to act as Chairperson or if no director is present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, the members present shall choose one of their members to be Chairperson of the meeting.

15.4 In case of a One Person Company—

(i) the resolution required to be passed at the general meetings of the company shall be deemed to have been passed if the resolution is agreed upon by the sole member and communicated to the company and entered in the minutes book maintained under section 118;

(ii) such minutes book shall be signed and dated by the member;

(iii) the resolution shall become effective from the date of signing such minutes by the sole member.

Adjournment of
meeting

16 (i) The Chairperson may, with the consent of any meeting at which a quorum is present, and shall, if so directed by the meeting, adjourn the meeting from time to time and from place to place.

(ii) No business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place.

(iii) When a meeting is adjourned for thirty days or more, notice of the adjourned meeting shall be given as in the case of an original meeting.

(iv) Save as aforesaid, and as provided in section 103 of the Act, it shall not be necessary to give any notice of an adjournment or of the business to be transacted at an adjourned meeting.

Voting rights

17 Subject to any rights or restrictions for the time being attached to any class or classes of shares,—

(a) on a show of hands, every member present in person shall have one vote; and

(b) on a poll, the voting rights of members shall be in proportion to his share in the paid-up equity share capital of the company.

- 17.1 A member may exercise his vote at a meeting by electronic means in accordance with section 108 and shall vote only once.
- 17.2 (i) In the case of joint holders, the vote of the senior who tenders a vote, whether in person or by proxy, shall be accepted to the exclusion of the votes of the other joint holders.
(ii) For this purpose, seniority shall be determined by the order in which the names stand in the register of members.
- 17.3 A member of unsound mind, or in respect of whom an order has been made by any court having jurisdiction in lunacy, may vote, whether on a show of hands or on a poll, by his committee or other legal guardian, and any such committee or guardian may, on a poll, vote by proxy.
- 17.4 Any business other than that upon which a poll has been demanded may be proceeded with, pending the taking of the poll.
- 17.5 No member shall be entitled to vote at any general meeting unless all calls or other sums presently payable by him in respect of shares in the company have been paid.
- 17.6 i) No objection shall be raised to the qualification of any voter except at the meeting or adjourned meeting at which the vote objected to is given or tendered, and every vote not disallowed at such meeting shall be valid for all purposes.

(ii) Any such objection made in due time shall be referred to the Chairperson of the meeting, whose decision shall be final and conclusive.

Proxy

- 18 The instrument appointing a proxy and the power-of-attorney or other authority, if any, under which it is signed or a notarised copy of that power or authority, shall be deposited at the registered office of the company not less than 48 hours before the time for holding the meeting or adjourned meeting at which the person named in the instrument proposes to vote, or, in the case of a poll, not less than 24 hours before the time appointed for the taking of the poll; and in default the instrument of proxy shall not be treated as valid.
- 18.1 An instrument appointing a proxy shall be in the form as prescribed in the rules made under section 105.
- 18.2 A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy shall be valid, notwithstanding the previous death or insanity of the principal or the revocation of the proxy or of the authority under which the proxy was executed, or the transfer of the shares in respect of which the proxy is given:

Provided that no intimation in writing of such death, insanity, revocation or transfer shall have been received by the company at its office before the commencement of the meeting or adjourned meeting at which the proxy is used.

- Board of Directors 19 The number of the directors and the names of the first directors shall be determined in writing by the subscribers of the memorandum or a majority of them.
- 19.1 (i) The remuneration of the directors shall, in so far as it consists of a monthly payment, be deemed to accrue from day-to-day.
(ii) In addition to the remuneration payable to them in pursuance of the Act, the directors may be paid all travelling, hotel and other expenses properly incurred by them—
(a) in attending and returning from meetings of the Board of Directors or any committee thereof or general meetings of the company; or
(b) in connection with the business of the company.
- 19.2 The Board may pay all expenses incurred in getting up and registering the company.
- 19.3 The company may exercise the powers conferred on it by section 88 with regard to the keeping of a foreign register; and the Board may (subject to the provisions of that section) make and vary such regulations as it may think fit respecting the keeping of any such register.
- 19.4 All cheques, promissory notes, drafts, *hundis*, bills of exchange and other negotiable instruments, and all receipts for monies paid to the company, shall be signed, drawn, accepted, endorsed, or otherwise executed, as the case may be, by such person and in such manner as the Board shall from time to time by resolution determine.
- 19.5 Every director present at any meeting of the Board or of a committee thereof shall sign his name in a book to be kept for that purpose.
- 19.6 (i) Subject to the provisions of section 149, the Board shall have power at any time, and from time to time, to appoint a person as an additional director, provided the number of the directors and additional directors together shall not at any time exceed the maximum strength fixed for the Board by the articles.
(ii) Such person shall hold office only up to the date of the next annual general meeting of the company but shall be eligible for appointment by the company as a director at that meeting subject to the provisions of the Act.
- 19.7 (i) The Board of Directors may meet for the conduct of business, adjourn and otherwise regulate its meetings, as it thinks fit.
(ii) A director may, and the manager or secretary on the requisition of a director shall, at any time, summon a meeting of the Board.
- 19.8 (i) Save as otherwise expressly provided in the Act, questions arising at any meeting of the Board shall be decided by a majority of votes.
(ii) In case of an equality of votes, the Chairperson of the

Board, if any, shall have a second or casting vote.

- 19.9 The continuing directors may act notwithstanding any vacancy in the Board; but, if and so long as their number is reduced below the quorum fixed by the Act for a meeting of the Board, the continuing directors or director may act for the purpose of increasing the number of directors to that fixed for the quorum, or of summoning a general meeting of the company, but for no other purpose.
- 19.10 (i) The Board may elect a Chairperson of its meetings and determine the period for which he is to hold office.
(ii) If no such Chairperson is elected, or if at any meeting the Chairperson is not present within five minutes after the time appointed for holding the meeting, the directors present may choose one of their number to be Chairperson of the meeting.
- 19.11 (i) The Board may, subject to the provisions of the Act, delegate any of its powers to committees consisting of such member or members of its body as it thinks fit.
(ii) Any committee so formed shall, in the exercise of the powers so delegated, conform to any regulations that may be imposed on it by the Board.
- 19.12 (i) A committee may elect a Chairperson of its meetings.
(ii) If no such Chairperson is elected, or if at any meeting the Chairperson is not present within five minutes after the time appointed for holding the meeting, the members present may choose one of their members to be Chairperson of the meeting.
- 19.13 (i) A committee may meet and adjourn as it thinks fit.
(ii) Questions arising at any meeting of a committee shall be determined by a majority of votes of the members present, and in case of an equality of votes, the Chairperson shall have a second or casting vote.
- 19.14 All acts done in any meeting of the Board or of a committee thereof or by any person acting as a director, shall, notwithstanding that it may be afterwards discovered that there was some defect in the appointment of any one or more of such directors or of any person acting as aforesaid, or that they or any of them were disqualified, be as valid as if every such director or such person had been duly appointed and was qualified to be a director.
- 19.15 Save as otherwise expressly provided in the Act, a resolution in writing, signed by all the members of the Board or of a committee thereof, for the time being entitled to receive notice of a meeting of the Board or committee, shall be valid and effective as if it had been passed at a meeting of the Board or committee, duly convened and held.
- 19.16 In case of a One Person Company—
(i) where the company is having only one director, all the businesses to be transacted at the meeting of the Board shall be entered into minutes book maintained under section 118;
(ii) such minutes book shall be signed and dated by the

director;

(iii) the resolution shall become effective from the date of signing such minutes by the director.

Chief Executive Officer, Manager, Company Secretary or Chief Financial Officer	20	<p>Subject to the provisions of the Act,—</p> <p>(i) A chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer may be appointed by the Board for such term, at such remuneration and upon such conditions as it may think fit; and any chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer so appointed may be removed by means of a resolution of the Board;</p> <p>(ii) A director may be appointed as chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer.</p> <p>20.1 A provision of the Act or these regulations requiring or authorizing a thing to be done by or to a director and chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer shall not be satisfied by its being done by or to the same person acting both as director and as, or in place of, chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer.</p>
The Seal	21	<p>(i) The Board shall provide for the safe custody of the seal.</p> <p>(ii) The seal of the company shall not be affixed to any instrument except by the authority of a resolution of the Board or of a committee of the Board authorized by it in that behalf, and except in the presence of at least two directors and of the secretary or such other person as the Board may appoint for the purpose; and those two directors and the secretary or other person aforesaid shall sign every instrument to which the seal of the company is so affixed in their presence.</p>
Dividends and Reserve	22	<p>The company in general meeting may declare dividends, but no dividend shall exceed the amount recommended by the Board.</p> <p>22.1 Subject to the provisions of section 123, the Board may from time to time pay to the members such interim dividends as appear to it to be justified by the profits of the company.</p> <p>22.2 (i) The Board may, before recommending any dividend, set aside out of the profits of the company such sums as it thinks fit as a reserve or reserves which shall, at the discretion of the Board, be applicable for any purpose to which the profits of the company may be properly applied, including provision for meeting contingencies or for equalizing dividends; and pending such application, may, at the like discretion, either be employed in the business of the company or be invested in such investments (other than shares of the company) as the Board may, from time to time, think fit.</p> <p>(ii) The Board may also carry forward any profits which it may consider necessary not to divide, without setting them aside as a reserve.</p>

- 22.3 (i) Subject to the rights of persons, if any, entitled to shares with special rights as to dividends, all dividends shall be declared and paid according to the amounts paid or credited as paid on the shares in respect whereof the dividend is paid, but if and so long as nothing is paid upon any of the shares in the company, dividends may be declared and paid according to the amounts of the shares.
- (ii) No amount paid or credited as paid on a share in advance of calls shall be treated for the purposes of this regulation as paid on the share.
- (iii) All dividends shall be apportioned and paid proportionately to the amounts paid or credited as paid on the shares during any portion or portions of the period in respect of which the dividend is paid; but if any share is issued on terms providing that it shall rank for dividend as from a particular date such share shall rank for dividend accordingly.
- 22.4 The Board may deduct from any dividend payable to any member all sums of money, if any, presently payable by him to the company on account of calls or otherwise in relation to the shares of the company.
- 22.5 (i) Any dividend, interest or other monies payable in cash in respect of shares may be paid by cheque or warrant sent through the post directed to the registered address of the holder or, in the case of joint holders, to the registered address of that one of the joint holders who is first named on the register of members, or to such person and to such address as the holder or joint holders may in writing direct.
- (ii) Every such cheque or warrant shall be made payable to the order of the person to whom it is sent.
- 22.6 Any one of two or more joint holders of a share may give effective receipts for any dividends, bonuses or other monies payable in respect of such share.
- 22.7 Notice of any dividend that may have been declared shall be given to the persons entitled to share therein in the manner mentioned in the Act.
- 22.8 No dividend shall bear interest against the company.

Accounts

- 23 (i) The Board shall from time to time determine whether and to what extent and at what times and places and under what conditions or regulations, the accounts and books of the company, or any of them, shall be open to the inspection of members not being directors.
- (ii) No member (not being a director) shall have any right of inspecting any account or book or document of the company except as conferred by law or authorized by the Board or by the company in general meeting.

Winding up	24	<p>Subject to the provisions of Chapter XX of the Act and rules made thereunder—</p> <p>(i) If the company shall be wound up, the liquidator may, with the sanction of a special resolution of the company and any other sanction required by the Act, divide amongst the members, in specie or kind, the whole or any part of the assets of the company, whether they shall consist of property of the same kind or not.</p> <p>(ii) For the purpose aforesaid, the liquidator may set such value as he deems fair upon any property to be divided as aforesaid and may determine how such division shall be carried out as between the members or different classes of members.</p> <p>(iii) The liquidator may, with the like sanction, vest the whole or any part of such assets in trustees upon such trusts for the benefit of the contributories if he considers necessary, but so that no member shall be compelled to accept any shares or other securities whereon there is any liability.</p>
Indemnity	25	<p>Every officer of the company shall be indemnified out of the assets of the company against any liability incurred by him in defending any proceedings, whether civil or criminal, in which judgment is given in his favour or in which he is acquitted or in which relief is granted to him by the court or the Tribunal.</p>

FPC TRAINING PROGRAM SCHEDULE

TRAINING SCHEDULE FOR DIRECTORS

Day 1:

- Registration of FPC directors and introduction with each other.
- Emergence of the concept of FPC.
- Basic knowledge/ terminology for understanding of FPC.
- Purpose of FPC formation and it's importance to establish the agriculture value chain.
- Methods of Joining Members/ Share holders in the FPC.
- Physical Activity.

Day 2:

- Knowledge about the climate change effects on Crops and introduction about climate resilient agriculture & horticulture activities
- Knowledge about the New Technology of Farming and introduction to SAMAK model of agriculture & agriculture residues management (Ex-Situ & In-Situ)
- Knowledge about Hard to Smart Farming Techniques.
- Basic Concept of Compliances for FPC

Day 3:

- Providing Knowledge about new machinery for Farming.
- Providing basic knowledge about the agri-entrepreneurship.
- Providing Knowledge about farmer friendly schemes and it's convergence with the FPCs.
- Field visit to a successful FPC

Note: 1- Duration of training: 3 days

2- Total expenditures: Rs 8,000=00 per trainee

3- Venue: SIAM, Rahman Khera, Lucknow.

4- Participants per batch: 20-25

FPC TRAINING PROGRAM SCHEDULE
TRAINING SCHEDULE FOR CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Day 1:

- Registration of FPC Chief Executive Officers and introduction with each other.
- Emergence of the concept of FPC.
- Purpose of FPC formation and it's importance to establish the agriculture value chain
- Basic knowledge/ terminology for understanding of FPC & role of CEOs
- Methods of Joining Members/ Share holders in the FPC.
- Physical Activity

Day 2:

- Compliances of FPC and it's importance for the continuity of the FPC & awareness about financial penalties
- Book Keeping for FPC
- Sample and activity for Understanding basic Concept of accounts.
- Collection of primary data to develop the detail business plan of the FPC

Day 3:

- Formulation of detail bankable business plan: a model presentation.
- Basic Introduction to Computer for Making Digital business approach
- Sample and activity for Understanding Digital platform.
- Field visit to successful FPC
-

- Note:**
- 1- Duration of training: 3 days
 - 2- Total expenditures: Rs 12,000=00 per trainee
 - 3- Venue: SIAM, Rahman Khera, Lucknow.
 - 4- ATM & BTM may also join the programme.
 - 5- Participants per batch: 20-25